



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खंड (ii).
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 252]
No. 252]

नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 15, 1997/चैत्र 25, 1919
NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 15, 1997/CHAITRA 25, 1919

वित्त मंत्रालय
(आर्थिक कार्य विभाग)
(बैंकिंग प्रभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 अप्रैल, 1997

का. आ. 328 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने पोत परिवहन विकास निधि समिति (उत्सादन) अधिनियम, 1986 (1986 का 66) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग, बैंकिंग प्रभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी की गई तारीख 3 अप्रैल, 1987, 22 सितम्बर, 1988 और 12 अप्रैल, 1993 का अधिसूचनाओं द्वारा शिपिंग क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कम्पनी आफ इण्डिया लिमिटेड (जिसे अब एस सी आई के नाम से जाना जाता है) जो कम्पनी अधिनियम 1956 के अधीन एक निगमित कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय इस समय 141 मेकर टॉवर "एफ" कफ परेड, मुम्बई 400005 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात एस सी आई सी आई" कहा गया है) को एक पदामिहित व्यक्ति नियुक्त किया था। और शिपिंग विकास निधि समिति द्वारा इसके उत्सादन से पूर्ण उक्त अधिनियम की धारा 4, धारा 5 और धारा 8 के अधीन तथा यथा और विशिष्टतया उक्त अधिसूचनाओं में उपवर्णित प्रयोज्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए की गई संविदाओं के मामले में अपनी शक्तियों और कृत्यों को एस.सी.आई.सी.आई. को प्रत्यायोजित किया था।

अब, केन्द्रीय सरकार, पोत परिवहन विकास निधि समिति (उत्सादन) अधिनियम, 1986 (1986 का 66) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय,

आर्थिक कार्य विभाग, (बैंकिंग प्रभाग) की अधिसूचनाओं को का.आ. 305(अ) तारीख 3 अप्रैल, 1987 का.आ. 882(अ), तारीख 20 सितम्बर, 1988 (22 सितम्बर, 1988 को प्रकाशित) और का.आ. 235(अ) तारीख 12 अप्रैल, 1993 का अधिक्रमण करते हुए, सिद्धांत उन बातों के जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है इण्डस्ट्रियल क्रेडिट एण्ड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड को जो भारतीय कम्पनी अधिनियम, 1913 (1913 का अधिनियम 7) के अधीन एक निगमित कम्पनी है और जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय 163, बेकम्बे रिक्लेसेशन मुम्बई-400020 में है (जिसे इसमें इसके पश्चात "आई सी आई सी आई कहा गया है) को इसके द्वारा एस सी आई सी आई के स्थान पर अपना पदानिहित व्यक्ति नियुक्त करती है। और उक्त अधिनियम की धारा 4, धारा 5 और धारा 8 के अधीन प्रयोज्य शक्तियों और कृत्यों को आई.सी.आई.सी.आई. को प्रत्यायोजित करती है, अर्थात्

- (1) उत्सादन से पूर्व, नौवहन विकास निधि समिति और शिपयाडों या पोतनिर्माताओं के बीच सम्पन्न संविदाओं की शर्तों के अनुसार, पोत निर्माण का प्रत्येक चरण पूरा हो जाने पर शिपयाडों या पोत निर्माताओं को नौवहन कम्पनी और शिपयाडों को, जैसी भी स्थिति हो, अथवा पोतनिर्माता को भुगतान इस शर्त के अधीन किया जाएगा कि प्रथम चरण के अन्त में भुगतान की राशि जारी करने से पूर्व, अभिहित व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय सरकार से पूर्वानुमोदन प्राप्त कर लिया जाएगा;
- (2) नौवहन विकास निधि समिति के उत्सादन से पूर्व, समिति द्वारा किये गये ऐसे भुगतानों के लिए, जिसके संबंध में संदिग्धित दायित्व भी विद्यमान हों, समर्थनकारी रूपया ऋणों का भुगतान इस शर्त पर किया जाएगा कि मूलधन और ब्याज

को चुकौती के मामले में, नौवहन कम्पनी की ओर से कोई चूक नहीं की गयी है अथवा चूक की स्थिति में केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित पुनरुद्धार की किसी योजना के अनुसार किस्तों का पुनर्निर्धारण कर दिया गया है;

- (3) नौवहन विकास निधि समिति के उत्पादन से पूर्व, समिति द्वारा निष्पादित गारंटियों अथवा प्रतिगारंटियों के संबंध में विदेशी शिपयार्ड से आस्थगित याई ऋणों के बारे में किसी हिताधिकारी द्वारा गारंटी अथवा प्रतिगारंटी का सहारा लिये जाने की सूरत में रकमों का भुगतान;

स्पष्टीकरण :—खंड (1), खंड (2), और खंड (3) में निर्दिष्ट संदायों/संवितरण से ऐसे संदाय/संवितरण अभिप्रेत है जो केन्द्रीय सरकार की ओर से आई.सी.आई.सी.आई. द्वारा इन प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों में से ही किए जाएंगे।

- (4) नौवहन विकास निधि समिति के उत्पादन से पूर्व समिति द्वारा निष्पादित संविदाओं से उत्पन्न पूरक ऋण करारों, प्रसंविदा विलेखों, सांविधिक बंधन विलेखों, उपक्रम विलेखों, त्रिपक्षीय करारों और बंधन मुक्ति विलेखों का निष्पादन;
- (5) पोत निर्माताओं और शिपयार्डों ऋण पोतों और ऋण ट्रालरों की सुपुर्दगी को स्वीकार्यता;
- (6) केन्द्रीय सरकार के पूर्वानुमोदन से किसी नौवहन कम्पनी के निदेशक बोर्ड में मनोनीत निदेशकों की नियुक्ति;
- (7) विदेशों से पोत प्राप्त करने की नयी योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा मंजूरी जारी किये जाने पर नौवहन कम्पनियों को सब्सिडी जारी करना;
- (8) नौवहन विकास निधि समिति द्वारा उत्पादन से पूर्व निष्पादित अस्तित्वयुक्त संविदाओं के संबंध में किसी नौवहन कम्पनी से प्राप्त प्रतिभूति प्रस्तावों की जांच और स्वीकार्यता;
- (9) चूक न होने की स्थिति में नौवहन कम्पनी का बीमा दावों के बारे में "अनापत्ति पत्र" जारी करना;
- (10) पात्र मत्स्य कंपनियों को मत्स्य जलयानों पर भारत सरकार के पत्र में या उक्त कम्पनियों की कामकाज पूंजी को पूरा करने के लिए किसी अन्य उधारदाता के पक्ष में प्रथम प्रभार के बाद की पंक्ति वाले प्रभार या बंधक के सृजन या किसी अस्तित्वयुक्त प्रभार के सृजन के लिए निम्नलिखित शर्तों के अधीन अनुज्ञा प्रदान करने की शक्ति :—

(क) दूसरा या बाद का बंधकदार तब तक उक्त दूसरा या पश्चात्पूर्व प्रभार या बंधक प्रवर्तित नहीं करेगा या उसके अधीन किन्हीं अधिकारों का प्रयोग नहीं करेगा, जब तक कि उक्त मत्स्य कंपनी भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में सृजित पहले बंधकदार या अस्तित्वयुक्त बंधक (बंधकों) द्वारा प्रतिभूत संपूर्ण रकम और उस पर ब्याज का संदाय नहीं कर देती।

(ख) केन्द्रीय सरकार को उपर्युक्त दूसरी या पश्चात्पूर्व बंधक को प्रभावी करने वाले सभी दस्तावेजों के संबंध में पुष्टिकर्ता पक्षकार बनाया जाएगा;

(ग) ऐसे बंधकों के दस्तावेज केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं और केन्द्रीय सरकार द्वारा किए गए अनुबंध इन दस्तावेजों में सम्मिलित किए जाते हैं, और

(घ) पहले बंधकदार के रूप में केन्द्रीय सरकार के अधिकारों पर किसी भी रीति से प्रतिकूल प्राभाव नहीं पड़ता या जोखिम नहीं होता;

स्पष्टीकरण : इस खंड के प्रयोजनों के लिए "पात्र मत्स्य कंपनी" से ऐसी मत्स्य कंपनी अभिप्रेत है जिसके (I) परिचालनों को अर्थक्षम माना जाता है, (II) लेखाओं का संचालन संतोषजनक समझा जाता है और (III) जिसका रवैया अनुशासनहीन/असहयोगपूर्ण नहीं है।

- (11) पोतपरिवहन कंपनियों या मत्स्य कंपनियों द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, ऋण तथा बंधक दस्तावेजों और बीमा पालिसियों के निबंधन और शर्तों के अनुसार समुद्री, युद्ध जोखिम और सुरक्षा तथा क्षतिपूर्ति कवर के संबंध में किए जाने वाले संदायों पर नजर रखना और उन मामलों में, जिनमें यथा स्थिति, उक्त पोतपरिवहन कंपनियों और मत्स्य कंपनियों, ने प्रीमियम के, जो प्रत्येक पोतपरिवहन कंपनी या मत्स्य कंपनी के लिए हर तीन महीने के बाद अधिकतम दस लाख रुपए हो, संदाय में व्यतिक्रम किया हो, पूर्वोक्त कवरों का नवीकरण करना, परन्तु जहां संदाय में व्यतिक्रम हुआ है वहीं ऐसे व्यतिक्रम के मामलों का केन्द्रीय सरकार की जानकारी में लाया जाएगा ताकि वह सरकार, यथास्थिति, ऐसी पोतपरिवहन कम्पनी या मत्स्य कंपनी, की वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने में समर्थ हो सके।
- (12) पोत निर्माताओं और पोत परिवहन कंपनी या मत्स्य कंपनी द्वारा दी गई बैंक गारंटियों को अभिरक्षा में रखना और इस बात की निगरानी रखना और यह सुनिश्चित करना कि पूर्वोक्त अधिनियम के अधीन पोत परिवहन विकास निधि समिति द्वारा अपने उत्पादन से पूर्व किए गए प्रत्येक ऋण करार के अधीन दिए गए ऋणों के किए प्रतिभूतियों की अपेक्षाओं के अनुसार इनका नवीकरण किया जाए और यदि आवश्यक हो, तो उक्त गारंटियों का अवलंब लेना,
- (13) ऐसे अनुवर्ती उपाय करने के लिए जो परिस्थितियों के अधीन यथोचित समझे जाए, पोत परिवहन और मत्स्य कंपनियों को पूर्व या आंशिक रूप से देय राशियों के संबंध में, उनके देय होने से पहले या बाद में, नोटिस जारी करना;
- (14) भारत में अथवा विदेशों में न्यायालयों और विधिक रूप से मान्यताप्राप्त किन्हीं अन्य प्राधिकारियों के समक्ष भूतपूर्व पोतपरिवहन विकास निधि समिति अथवा केन्द्रीय सरकार की सहायता से पोत-परिवहन और मत्स्य कंपनियों से संबंधित मामलों में केन्द्रीय सरकार के पदाभिहित व्यक्ति के रूप में मामलों में हस्तक्षेप करना;
- (15) भूतपूर्व पोत-परिवहन विकास निधि समिति अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा यथास्थिति, पोतपरिवहन कंपनियों या मत्स्य

- कंपनियों को दिए गए ऋण से संबंधित सभी विधिक दस्तावेजों को निष्पादित करना और अभिरक्षा में रखना;
- (16) पोत-परिवहन कंपनियों अथवा मत्स्य कंपनियों को भूतपूर्व पोत-परिवहन विकास निधि समिति द्वारा या केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में गारंटी की पर्याप्तता का पुनर्विलोकन करना और, निष्पादित दस्तावेजों के निर्बंधनों के अनुसार अतिरिक्त या आनुकूलिक गारंटी के बारे में केन्द्रीय सरकार के अनुबंधों का उक्त कंपनियों द्वारा अनुपालन सुनिश्चित किया जाना;
- (17) प्रत्येक पोत-परिवहन और मत्स्य कंपनी के बारे में बकाया देय राशियों, अतिदेय राशियों और संवितरणों को दर्शाने वाली विस्तृत लेखा बहियों, रजिस्ट्रारों और अन्य सुसंगत अभिलेखों को रखना;
- (18) संविदाओं के बारे में पुनर्वास प्रस्थापनाओं का कार्यान्वयन और उन्हें ऐसी पोत-परिवहन कंपनियों या मत्स्य कंपनियों को संसूचित करना जैसी केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर अनुमोदित की जाएं;
- (19) पोत-परिवहन और मत्स्य कंपनियों के बारे में ऐसे पुनर्वास प्रस्थापनाओं का वार्षिक पुनर्विलोकन करना और केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से ऐसी पुनर्वास प्रस्थापनाओं में उपान्तरण करना;
- (20) संबद्ध पोत-परिवहन और मत्स्य कंपनियों के बकाया ऋण की तुष्टि के लिए जलयानों के विक्रय और किसी भी प्रकार की प्राप्तियों का केन्द्रीय सरकार के प्रति विनियोजन और उक्त कंपनियों को उसकी संसूचना। परंतु किसी विशिष्ट मामले में अथवा मामलों के वर्ष में केन्द्रीय सरकार उक्त सभी या किन्हीं शक्तियों और कृत्यों का स्वयं प्रयोग कर सकता है।

परन्तु केन्द्रीय सरकार, किसी विशिष्ट मामले या मामलों के वर्ग में उक्त शक्तियों में से किसी अथवा सभी शक्तियों और कृत्यों का स्वयं प्रयोग कर सकेगी।

इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तारीख तक पदाभिहित व्यक्तियों के रूप में एस.सी.आई.सी.आई. द्वारा की गई सभी कार्रवाई विलेख, और बातें तथा निष्पादित किए गए सभी करार विलेख, संविदाएं और लिखित सभी आशयों और प्रयोजनों के लिए विधिमान्य प्रभावी और बाह्यकारी तथा सभी सम्बद्ध पक्षकारों के लिए और उनके विरुद्ध होगी।

इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तारीख से व्यक्ति के रूप में पदाभिहित एस.सी.आई.सी.आई. के बजाय आई.सी.आई.सी.आई. को उसके स्थान पर प्रभावी रूप से रखा जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप, आई.सी.आई.सी.आई. उपरोक्त शक्तियों और कृत्यों के प्रयोग से संबंधित सभी मामलों में एस.सी.आई.सी.आई. के स्थान पर प्रतिस्थापित होगी और प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी और एस.सी.आई.सी.आई. में निहित सभी शक्तियां, अधिकार और अनुमोदन और आई.सी.आई.सी.आई. में निहित होंगे और निहित हुए समझे जाएंगे और आई.सी.आई.सी.आई. समस्त विलेखों, दस्तावेजों और उनसे संबंधित लिखितों में जिसके अंतर्गत परिसीमा के बिना

ऐसे विलेख और लिखित भी हैं, जो पदाभिहित व्यक्ति के रूप में अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए एस.सी.आई.सी.आई. द्वारा किए गए हैं, इसके पक्षकारों द्वारा किसी और कार्रवाई की अपेक्षा किए बिना पक्षकार के रूप में एस.सी.आई.सी.आई. को प्रतिस्थापित करेगी और प्रतिस्थापित की गई समझी जाएगी।

यह अधिसूचना तारीख 15 अप्रैल, 1997 से प्रभावी होगी।

[फा. सं. 1/14/96-आई. एफ.-एस.-भाग]

ए. के. जैन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
(Banking Division)
NOTIFICATION

New Delhi, the 15th April, 1997

S. O. 328 (E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16 of the Shipping Development Fund Committee (Abolition) Act, 1986 (66 of 1986), the Central Government vide notifications dated the 3rd day of April, 1987, the 22nd day of September 1988 and the 12th day of April, 1993 issued by the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, Banking Division, New Delhi, had appointed, The Shipping Credit and Investment Company of India Limited (now known as SCICI Limited), a company incorporated under the Companies Act, 1956, and presently having its registered office at 141, Maker Tower 'F' Cuffe Parade, Mumbai-400 005 (hereinafter referred to as "SCICI"), as designated person and had delegated to SCICI its powers and functions in respect of contracts entered into by the Shipping Development Fund Committee prior to its abolition exercisable under Sections 4, 5, and 8 of the said Act, and as more particularly set out in the said notifications.

Now, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 16 of the Shipping Development Fund Committee (Abolition) Act, 1986 (66 of 1986) and in supersession of notifications of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs (Banking Division) vide S.O. 305 (E) dated the 3rd April, 1987, S.O. 882 (E) dated 20th September 1988 (published on 22nd September 1988) and S.O. 235 (E) dated 12th April, 1993, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby appoints The Industrial Credit and Investment Corporation of India Limited, a company incorporated under the Indian Companies Act 1913 (Act VII of 1913) and having its registered office at 163 Backbay Reclamation, Mumbai-400 020 (hereinafter referred to as "ICICI") as its designated person in place of SCICI, and delegates to ICICI, the powers and functions as exercisable under Sections 4, 5 and 8 of the Act, namely:—

- (1) Payments to shipyards or shipbuilders at the conclusion of each stage of shipbuilding in accordance with terms and conditions of contracts entered into between the Shipping Development Fund Committee before its abolition, the concerned shipping concern and the Shipyard

- as the case may be or, the shipbuilder, subject to the condition that prior approval of the Central Government shall be obtained by the designated person before releasing payment at the end of the first stage;
- (2) disbursement of rupee back-up loans in cases where contractual liability for such payments incurred by the Shipping Development Fund Committee before its abolition still subsists, subject to the condition that there is no default on the part of the shipping concern in the matter of repayment of the principal and interest or in case of default, the instalments have been allowed to be rescheduled in accordance with any scheme of rehabilitation approved by the Central Government;
 - (3) payment of amounts in respect of the guarantees or counter guarantees entered into by the Shipping Development Fund Committee before its abolition in relation to deferred yard credit from foreign shipyards as and when a guarantee or counter guarantee is invoked by a beneficiary;
Explanation: The payments/disbursements referred to clauses (1), (2) and (3) means the payments/disbursements which shall be made by ICICI on behalf of the Central Government only out of funds made available by the Central Government for these purposes.
 - (4) execution of Supplemental Loan Agreements, Deeds of Covenants, Deeds of Statutory Mortgages, Deeds of Undertakings, Tripartite Agreements and Deeds of Release of Mortgages arising out of contracts entered into by the Shipping Development Fund Committee prior to its abolition;
 - (5) acceptance of delivery of loan ships and loan trawlers from shipbuilders and shipyards;
 - (6) appointment of nominee Directors on the Board of a shipping concern with the prior approval of the Central Government;
 - (7) release of subsidy in terms of The Ship Acquisition from Abroad Under New Scheme (SAFAUNS) to shipping concerns on the issuance of Government sanction;
 - (8) examination and acceptance of security proposals received from any shipping concern in respect of subsisting contracts entered into by the Shipping Development Fund Committee prior to its abolition;
 - (9) issuance of 'No Objection' Certificate to any shipping concern regarding insurance claims where the shipping concern is not in default;
 - (10) power to grant permission to eligible fishing companies for creation of a charge or mortgage ranking after the first charge or creation of any subsisting charge in favour of the Government of India on the fishing vessels or in favour of any other lender for meeting the said companies'

working capital subject to the following conditions:

- (a) the second or further mortgagee shall not enforce the said second or subsequent charge or mortgage or exercise any rights thereunder without the said fishing company paying off the entire amount and interest thereon secured by the first mortgage or subsisting mortgage(s) created in favour of the President of India;
 - (b) the Central Government shall be made a confirming party to all the documents effecting the above second or subsequent mortgage;
 - (c) the documents of such mortgage are approved by the Central Government and the stipulations made by Central Government are incorporated in these documents; and
 - (d) the right of Central Government as the first mortgagee are not adversely affected or jeopardised in any manner;
- Explanation:** For the purposes of this clause "An eligible fishing company" means a fishing company whose (i) operations are regarded as viable, (ii) the conduct of accounts is considered satisfactory and (iii) there is no recalcitrant/non-cooperative attitude.
- (11) to keep watch over the payments to be made by shipping companies or fishing companies, as the case may be, in respect of marine, war risk and protection and indemnity covers in accordance with the terms and conditions of the loan and mortgage documents and the insurance policies and renewal of the aforesaid covers in cases where the said shipping companies and fishing companies, as the case may be, are in default in payment of premium, subject to a maximum of Rupee Ten Lakhs for each shipping company or fishing company, after every three months, provided that where there is default in payment, the cases of such default shall be brought to the notice of the Central Government enabling that Government to review the financial position of such shipping company or fishing company, as the case may be;
 - (12) to hold custody of Bank Guarantees furnished by shipbuilders and shipping company or fishing company and to keep a watch and to ensure that these are renewed in accordance with the requirements of securities for the loans advanced under each loan agreement entered into by Shipping Development Fund Committee prior to its abolition under the aforesaid Act and to invoke the said guarantees, if necessary;
 - (13) to issue notices to shipping and fishing companies in respect of any dues either in full or in part before or after their having become due for taking such follow-up measures as are deemed expedient under the circumstances;
 - (14) to intervene in cases as designated person of the Central Government in cases related to shipping and fishing companies assisted by the erstwhile Shipping Development Fund Committee or by the Central Government before Courts as well as before any other legally recognised authorities either in India or abroad;

- (15) to execute and hold custody of all legal documents pertaining to the loan advanced by the erstwhile Shipping Development Fund Committee or by the Central Government to shipping companies or fishing companies as the case may be ;
- (16) review of the adequacy of security in respect of the loans advanced by the erstwhile Shipping Development Fund Committee or by the Central Government to shipping companies or fishing companies and ensuring compliance by the said companies of the stipulations of Central Government regarding additional or alternative security in terms of the executed documents;
- (17) maintenance of detailed books of accounts, registers and other relevant records showing outstanding dues, overdues and disbursements in respect of each shipping and fishing company;
- (18) implementation of rehabilitation proposals in respect of contracts and communication thereof to shipping companies or fishing companies as approved by the Central Government from time to time;
- (19) yearly review of such rehabilitation proposals in respect of shipping and fishing companies and carrying out modifications in such rehabilitation proposals with the approval of Central Government;
- (20) appropriation of sale proceeds of vessels and receipts of any other nature towards the satis-

faction of the outstanding debt of the concerned shipping and fishing companies to the Central Government and communication thereof of the said companies.

Provided that the Central Government may itself exercise any or all of the said powers and functions in any particular case or class of cases.

All acts, deeds and things done and all agreements, deeds, contracts and writings executed by SCICI as a designated person upto the date of bringing into force of this notification, shall be valid, effective and binding for all intents and purposes and for and against all parties concerned;

ICICI shall effectively substitute in place and stead of SCICI as designated person from the date of bringing into force of this notification. Consequent upon this, ICICI shall replace and shall be deemed to have replaced SCICI in all matters relating to the exercise of the aforesaid powers and functions, and all powers rights and approvals vested in SCICI shall be vested and shall be deemed to be vested in ICICI; and ICICI shall substitute and shall be deemed to have substituted SCICI as party to all deeds, documents and writings in relation thereto including, without limitation, such deeds, documents and writings as have been entered into by SCICI for the effective discharge of its functions as designated person, without requiring any further act or deed by the parties thereto.

This notification shall come into force on and from 15th April, 1997.

[F.No. 1/14/96-IF-S-Part]
A.K. JAIN, Jt. Secy.

